

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02

अंक - 138

जैनपुर, मंगलवार, 13 फरवरी 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

**संक्षिप्त खबरें**  
**मोदी सरकार ने 10 वर्ष में किसान को सिर्फ ठगा है - राहुल-प्रियंका**

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों को लेकर असंवेदनशील है और उसने 10 साल के कार्यकाल में किसानों को सिर्फ ठगा है और अब उनके रास्ते में कील काटें बिछाकर उनकी राह में अरोध पैदा किए जा रहे हैं। श्री गांधी ने कहा, "दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दो गुनी आमदानी का वादा कर मोदी ने अन्दाजाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महांगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके काजे 60 प्रतिशत बढ़ गए—इसी लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गांवाई। दो गोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति का सकता है न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं इनको दिल्ली से उत्तरांग फेंगे, किसान का न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। किसानों के रास्ते में कील-काटे बिछाना अमृतनाल है या अन्यकाल। इसी असंवेदनशील एवं खेती करने वाले देना - कैसी सरकार का लक्षण है।

**रेलवे ने सुरंग बनाने के लिए स्विस कंपनियों से की साझेदारी**

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे ने ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग नई रेल लाइन और ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक समेत विभिन्न परियोजनाओं में सुरंग बनाने के काम के लिए रियर्टर्जरलैंड की कंपनियों से साझेदारी की है। रेलवे बोर्ड में तकनीकी सहयोग के लिए स्विस परियोजना के पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा और संचार (डीइटीईसी) के संघीय विभाग और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन विचाराधीन है। सरकार ने मौजूदा प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के लिए अपने विवेस के समकक्ष के साथ सहयोग करने के लिए विशेष रूप से हब एंड स्पोक मॉडल और सुरंग बनाने के उन्नत तकनीक के क्षेत्रों में क्या उपाय किए हैं? इस पर रेल मंत्री ने स्विस कंपनियों से साझेदारी की बात कहते हुए बताया कि रोलिंग स्टॉक, रेलवे बुनियादी ढांचा, रेल सुरक्षा, ड्रेन शेड्यूलिंग व परिचालन सुधार, नई प्रौद्योगिकी व नवाचार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों की पहचान की गई है। 125 किमी लंबी ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग परियोजना का विकास रेल विकास निगम लिमिटेड और ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना का विकास इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

## कोई भी राज्य या देश, विकास में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता - ममता बनर्जी

कोलकाता, एजेंसी। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है

रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ममता



बनर्जी ने दावा किया कि कोई भी राज्य या देश विकास के मामले में हमारा समाना नहीं कर सकता। ये भी तब हैं, जब केंद्र ने हमें विचित रखने की कोशिश की, लेकिन हम हमारे लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे महिलाओं ने हाल ही में विशेष प्रदर्शन किया और शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर लोगों की जमीन हड्डपने का आरोप लगाया था। महिलाओं ने ये भी दावा किया था कि शाहजहां शेख और टीएमसी नेताओं ने उनके साथ यूनियन उत्तीर्ण किया है। इस मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार उचित कदम उठा रही है। राज्य महिला आयोग की टीम को वहां जेजा गया है। समेत कई और घोटालों की जांच कर रही है। विपक्षी भाजपा भ्रष्टाचार बनर्जी ने ये भी दावा किया।

बनर्जी ने ये बातें कही। ममता बनर्जी के विकास के लिए कड़ी मेहनत की जारी की थी और उनके साथ कानेकंबड़ी के बावजूद राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के लिए लोगों के लिए कई कार्यक्रमों के लिए आयोजित करते हुए। ममता

# संपादकीय

# भारत की सफल कृषि नीति

कतर की जेल में बंद भारतीय नौसैनिकों को 18 महीने बाद जेल से रिहाई की सोमवार को जैसे ही खबर आई तो सारा देश ही झूम उठा। कुछ समय पहले इन अधिकारियों की मौत की सजा को अलग-अलग अवधि की जेल की सजा में बदल दिया गया था। तब देश को कम से कम यह संतोष तो था कि चलो हमारे नागरिकों की जान तो बच गई, पर देश यह भी प्रार्थना कर रहा था कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिक रिहा होकर सकुशल देश वापस आ जाएं। बेशक, इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी सफलता ही माना जाएगा कि कतर से फांसी की सजा घोषित हुए नागरिकों की आज रिहाई हो गई। वे सभी सकुशल और ससम्मान जनक तरीके से भारत की धरती पर वापस लौट आए। इस तरह से भारत की कुशल विदेश नीति को सारे संसार ने देखा और दांतों तले उंगलियाँ दबाकर आश्चर्य से देखते ही रह गये। अमूमन अरब देशों के शेष सामान्य तौर पर जासूसी के आरोप में सजा प्राप्त लोगों की सजा माफ नहीं करता। केन्द्र में मोदी सरकार के 2014 में गठन के बाद से भारत के अरब देशों के साथ संबंध लगातार सुधर रहे हैं। उसी के सार्थक परिणाम को भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और घर वापसी के रूप में देखा जाना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अबू धाबी में सनातन संस्कृति का भव्य मंदिर भी दुनिया देखेगी। ‘अगर मोदी जी नहीं होते तो हम हिंदुस्तान की सरजमीं पर आज नहीं खड़े हो पाते’। अपनी रिहाई से खुश एक नौसैनिक ने भारत आने पर भारत मां की जय बोलते हुए कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी ने खुद हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज हमारी रिहाई संभव नहीं थी। यह बड़ी उपलब्धि भारत के शक्तिशाली नेतृत्व का प्रभाव प्रमाण है। यह कूटनीतिक जीत 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। आज प्रधानमंत्री मोदी की सफल विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। देश किस तेजी से बदल रहा है, यह जानन को लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेरनयू) की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के उस बयान को देखना होगा। वो एक दौर में देश विरोधी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई थीं। उन्होंने भी जौ ऐचिन्टों की सिर्पार्क के तात्परोत्तम ऐचिन्टा

उन्हान ना ना सांपों का रहाइ के बाद ताराल नाउदा रस्टॉपगान एक्स पर लिखा, "मौत की सजा से घर वापसी तकरु यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने फिर असंभव को संभव कर दिखाया है। शांत रहें और विश्वास रखें। कतर से लौटे पूर्व नौसैनिकों के परिवार को बधाई।" तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से देश बदल रहा है। दरअसल, कतर के दोहा के अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के इन पूर्व जवानों को पिछले साल 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने राहत दी थी। अदालत ने तब अक्टूबर 2023 में इन्हें दी मौत की सजा को कम करते हुए 3 साल से लेकर 25 साल तक की अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी।

कतर का जल म बद भारताया का रहा से साफ ह एक अब जहा पर भी भारतवंशी या भारतीय संकट में होते हैं तो भारत सरकार हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठती। रस्स-यूक्रेन जंग के कारण हजारों भारतीय मेडिकल स्टुडेंट्स यूक्रेन में फंस गए थे। उन्हें भारत सरकार सुरक्षित स्वदेश लेकर आई। भारत के हजारों विद्यार्थी यूक्रेन में थे। वे वहां पर मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और दूसरे पेशेवर कोर्स कर रहे थे। ये रस्स-यूक्रेन जंग को देखते हुए वहां से निकल कर स्वदेश आना चाहते थे। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अधिक संख्या में यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में पढ़ रहे भारतीय नौजवानों को स्वदेश कैसा लाया जाएगा। पर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है।

पछले साल अफ्रिका का दश सूडान में सना आर अधसानक बल के बीच चल रहे भीषण गृहयुद्ध के चलते वहां हालात बद से बदतर हो गए थे। ऐसे में वहां फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने को लेकर सारा देश चिंतित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकासी के लिए विदेश मंत्रालय के अधि कारियों को निर्देश दिए। मतलब सरकार एकशन मोड में आ गई। कुछ ही हप्तों में वहां से सारे के सारे भारतीय सुरक्षित वापस स्वदेश आ गए। अब अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के दिनों को याद कर लें। भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया के विमान लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर स्वदेश आते रहे थे। काबुल में जिस तरह के हालात बन गए थे उसमें सारे भारतीयों को लेकर आना कोई छोटी बात नहीं थी। इनको ताजिकिस्तान के रास्ते दिल्ली या देश के अन्य भागों में लाया जा रहा था। कुछ विमान कतर के रास्ते भी आ रहे थे। भारत के अफगानिस्तान में दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, इनमें अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए भारत हर तरह की मदद भी कर रहा था। भारत के हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट भी इस अशांत माहौल में फंस गए। इनसे हजारों भारतीय जुड़े हुए थे। इन्हीं भारतीयों को निकाला जा रहा था। भारत की तरफ से अफगानिस्तान बांध से लेकर स्कूल, बिजली घर से लेकर सड़कें, काबुल की संसद से लेकर पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ सेक्टर समेत न जाने कितनी परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से देश के नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने और वहां से भारत आने के इच्छुक सिखों व हिंदुओं को शरण देने का अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये।

# सेना बनाम जनता

जब पाकिस्तानी सेना चुनाव पूर्व राजनीतिक घटनाक्रम का संचालन कर रही थी। इमरान खान और प्रमुख सहयोगियों को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया है, उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है और उनकी पार्टी पीटीआई को अलग कर दिया गया है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा सार्वजनिक चेतावनी कि चुनाव के संचालन में अनियमितताओं, हस्तक्षेप और कथित धोखाधड़ी की जांच की जानी चाहिए। यह जनता का पाखंडी रुख लगता है क्योंकि वे शायद ही चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा सत्ता में आएं। वे शायद ही इमरान खान की पाकिस्तानी विदेश नीति के अपहरण को भूल सकते हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध शुरू करने की विरोधी नीति के अपहरण के बावजूद नहीं। बाबर अंग्रेजों का दायरा जिसमें वह दूसरी बार बढ़ा गया था, उसमें अपहरण की विरोधी नीति के अपहरण के बावजूद नहीं। बाबर अंग्रेजों का दायरा जिसमें वह दूसरी बार बढ़ा गया था, उसमें अपहरण की विरोधी नीति के अपहरण के बावजूद नहीं।

# एक भारत रत्न ने बदली पश्चिम यूपी की राजनीति

## अशाक

कल तक विपक्ष आइ.एन.डा.आइ.बनाकर एकजुट दिखाते हुए ल्ली फतह करने की तैयारी में। अब भाजपा के बिहार के बाद ने में किए खेल में विपक्ष के सारे लोकरण बिगड़ गए। भाजपा की गुगली में विपक्ष धराशाही हो गई। बिहार का अभी नितीश कुमार भाजपा से गठबंधन का मामला नहीं पड़ा था कि भाजपा ने सान नेता चौधरी चरण सिंह को रत्न दे दिया। इस एक भारत से भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीति का नवशा बदलने में सम्याब हो गई। इस भारत रत्न ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता पूरी तरह से जड़े हीं हिलाकर दी। इस भारत रत्न से जहां जपा को सीधे लाभ मिलेगा, वहीं विपक्ष को भारी नुकसान होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों की में जाट आरक्षण की मांग को स पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाटों का काफी तबका भाजपा से जुड़ गया था। मुजफ्फर नगर के दंगे ने इसे और एकजुट किया। राम मंदिर के नाम पर तो ये धर्मीकरण और हुआ रालोद का परंपरागत वोट ही उसके पास बचा था। इस भारत रत्न के बाद भाजपा.रालोद गठबंधन से यह वोट भाजपा को लाभ ही पहुंचाएगा। अब तक का राजनीतिक दृश्य कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का गठबंधन नहीं होगा। बसपा सुप्रिमो सुश्री मायावती इसकी कई बार घोषणा कर चुकी हैं। इसपा पश्चिम में रालोद के साथ मिलकर भाजपा के सम्मुख मैदान में उत्तरने की तैयारी में थीं सीट भी तै हो गई थीं कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, पर ये राजनीति है। इसमें अगले पल क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये हो गया। किसान नेता चौधरी

चरणासह का भारत रत्न मिलन के बाद रालोद का भाजपा के साथ जाना सरल हो गया। रालोद के भाजपा के साथ जाने से पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे ही समीकरण बदल गए। तै हो गया कि पश्चिम का भाजपा दृ रालोद में बंटा 18 प्रतिशत जाट वोट सीधा अब रालोद भाजपा गठबंधन को जाएगा। सपा अब यहाँ कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएगी। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन से पहले इंकार कर दिया है। बाद में रालोद के साथ रहने के तौरान उहनें यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट देने की घोषणा की थी, अब बदले में हालात में रालोद के भाजपा के साथ जाने के बाद वे क्या करेंगे, यह समय ही बताएगा। अब तक कांग्रेस के सामने हेकड़ी दिखा रहे सपा सुप्रिमों अखिलेख का चुनावी समीकरण और गठबंधन कांग्रेस से अपनी शर्त पर होगा या कांग्रेस की

यह अभा नहा कहा जाकता, किंतु यह तै है कि अब तक का उसका कांग्रेस के प्रति कठोर रवैया जरूर मुलायम होगा। पिछले विधान सभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश ने सपा-रालोद गठबंधन के जाट-मुस्लिम समीकरण के बावजूद बीजेपी ने कुल 136 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर कब्जा किया था। पश्चिम यूपी की 22 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। पश्चिम यूपी में करीब 18 प्रतिशत जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एकमुश्त वोट पश्चिम यूपी में किसी भी दल की हार-जीत तय करता है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की सात सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत तीन सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। आरएलडी के भाजपा नीत गठबंधन एडीए के साथ आने से यहां बाजपा का जात का राह आसान हो जाएगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन के बाद उपर्युक्त किसान आक्रोश को कम करने के लिए भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी रालोद प्रमुख जयंत को साधने की कोशिश की थी, लेकिन वे उन्हें जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव में अपने मिशन को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत भाजपा को महसूस हो रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब यह खेला पूरा हो गया। यहां लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, सपा-बसपा महागठबंधन को आठ सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिम यूपी की चार सीटों पर सपा और चार पर बसपा उम्मीदवारों को जीत मिला। हालांकि, रालोद के इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिल सकी। जाट समाज ने भी रालोद का साथ नहीं दिया। 2014 के बाद 2019 में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ आई थी। जाट समाज के दिग्गज नेता अजित सिंह और जयंत चौधरी भी सपा-बसपा गठबंधन के साथ रहने के बाद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। एनडीए के साथ आने से आरएलडी की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। फायदा भाजपा को भी होना तय माना जा रहा है किंतु ये भी निश्चित है कि इस गठबंधन से शून्य पर पहुंची रालोद को भी संजीवनी मिलेगी। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों का गणित भाजपा-आरएलडी गठबंधन के बाद बदलना तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी की स्वीकार्यता हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बीच अपनी राजनीति शुरू की थी।

# उच्च पद पर बैठे लोगों ने राज्य और धर्म को अलग रखा

१९

एस्काट करत समय (चलत हुए, ना कि वह आग्रह करेंगे) राष्ट्रपति आर. मुगल गार्डन में नारायणन, इसे अभी भी कहा जाता था, ई भी उन विषयों पर चर्चा कर लता था जिन्हें अन्यथा सीमा से ऊर माना जा सकता था। संवैधानिक औचित्य, संवेदनशीलता और तेकता पर इस सबसे प्रबुद्ध माग की कार्यप्रणाली में फिल्टर अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शा एक विशेषाधिकार था। अंत्रपति के आर. नारायणन घटवादी, आत्मविश्वासी और गाल करने के लिए बेहद खुले वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य हिस्से के रूप में जवाबदेही और स्मेदारी के सिद्धांतों के प्रति स्पष्ट से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अदर्शता लाने के लिए राष्ट्रपति न की विज्ञप्तियों की शुरुआत थी और कठिन सवाल पूछने लिए जाने जाने वाले एक मुखर दाक को अपना साक्षात्कार लेने अनुमति दी थी। वह विदेश में उस समय का सरकार का आवश्यक जांच-और-संतुलन सदेश के हिस्से के रूप में, अपने स्वयं के संचार पर काम करने के लिए जाने जाते थे। जब भी उन्हें लगा कि संवैधानिक नैतिकता खतरे में है, उन्होंने धीरे से असहमति जताई, यद्यपि, जैसा कि उन्होंने कहा, "संवैधानिकता की चार दीवारों के भीतर"। वह "प्रथम दलित राष्ट्रपति" जैसे कृपालु और संरक्षण देने वाले लेबल से स्पष्ट रूप से असहज थे, क्योंकि राजनेताओं को मौजूदा सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यक्तियों को वर्गीकृत करना और व्यक्तियों को "रबर स्टांप" तक कम करना पसंद था। इसके बजाय, लेखक ने राष्ट्रपति भवन की अपनी यात्रा के महत्व को एक संपन्न लोकतंत्र में समानता की गवाही के रूप में बताया, जहां "मेरा जीवन समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को समायोजित करने और सशक्त बनाने की लोकतांत्रिक प्रणाली की क्षमता को समाहित करता है"। उन्हें दिए

लाए अपयोग्य आर निरक्त थे, जा  
एक पेशेवर के रूप में अपनी  
योग्यता, निष्ठा और सरासर प्रतिभा  
के कारण देश में सबसे महत्वपूर्ण  
पदों पर थे। अपनी युवावस्था में  
अकल्पनीय सामाजिक-आर्थिक  
कठिनाइयों के बावजूद, लंदन स्कूल  
ऑफ इकोनॉमिक्स में हेरोल्ड लास्की  
के पसंदीदा छात्र भारतीय विदेश  
सेवा में शामिल हो गए और देश  
के "सर्वश्रेष्ठ राजनयिक" के रूप में  
प्रतिष्ठित हुए।

पहल, नारायणन न उपराष्ट्रपात बनकर सभी संभावित कार्यालयों का चक्र पूरा किया। ऐसी त्रुटीहीन उपलब्धियों के साथ, नारायणन किसी के प्रति या किसी पक्षपातपूर्ण विचारधारा के प्रति आभारी नहीं थी, बल्कि केवल अपनी अंतरात्मा और उस पुस्तक के प्रति, जिसे वह वास्तव में सबसे पवित्र मानते थे रु भारत का संविधान। एक शाम, जब मैं उसे ले जा रहा था, मैंने पूछा कि वह धार्मिक स्थानों पर जाने या देवताओं या प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं से मिलने से क्यों बचता है? मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि अप्रत्याशित प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें कुछ सेकंड से अधिक समय लगा। कुछ सेकंड तक चुपचाप चलने के बाद, वह रुके और स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया क्योंकि उन्हें लगा कि संविधान और इसकी उच्च भावना के विवेक-रक्षक के रूप में, यह शायद सबसे अच्छा था। फिर उन्होंने धार्मिकता के अचेतन, लंबे विवादों धाराधा घावा का आर इशारा किया जो स्वाभाविक रूप से 5,000 साल की सम्यता में मौजूद है, और एक संवैधानिक व्यक्ति के रूप में, यह महत्वपूर्ण था कि वह परस्पर विरोधी धारणाओं के किसी भी पक्ष को महत्व नहीं दे रहे थे। हर धारणा समान रूप से मायने रखती है। उनके लिए कल्पित अतीत भविष्य की प्रगति को पटरी से उतार सकता है। के.आर. नारायणन वह दुर्लभ व्यक्ति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं गए या किसी भी धार्मिक आयोजन में कोई भूमिका नहीं निभाते हुए, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बारे में बात करते रहे। वह प्रकाशिकी की शक्ति के प्रति पूरी तरह सचेत थे और इसका उपयोग केवल समावेशिता, उपचार और सुधारों का सुझाव देने के लिए करते थे। उनकी निर्विवाद पृष्ठभूमि एक तथ्य थी, और फिर भी यह कड़वाहट, सुविधा जानक आव्हान या यहां तक कि प्रशंसा का साधन नहीं थी, बल्कि सभावनाओं का शक्ति का दाहरण के लिए थी, अगर ईमानदारी से इसका पालन किया जाए। उन्होंने संविधान के कुछ हिस्सों को खद्दम करने के संशोधनवाद, पुनर्कल्पना और पुनर्व्याख्या का प्रसिद्ध रूप से यह कहते हुए विरोध किया थारू “क्या संविधान ने हमें विफल कर दिया है या हमने संविधान को विफल कर दिया है?”। भारत के पास तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक समान रूप से प्रतिबद्ध संविधानवादी थे, जिन्होंने नारायणन के सूक्ष्म संदेश के महत्व को पहचानते हुए, चुपचाप बड़बड़ाहट को दबा दिया था। ऐसी स्थिति में जो अब अकल्पनीय लगती है, के.आर. नारायणन ने अक्सर पीएमओ को चिंताएं व्यक्त कीं और इन्हें दो लोगों द्वारा संभाला गया जो वास्तव में स्वरूप असहमति की आवश्यकता में विश्वास करते थे और दिन के अंत में मानते थे कि वे एक ही टीम में थे। यदि एक के पास अभिव्यक्ति में संवैधानिक शुद्धता की बाधाएं थीं।

# उत्तराखण्ड फिसलन भरी और स्वतरनाक राह पर चल रहा

लालत  
प्रविष्टि २१

याद आप पुरुष या माहला है, र “लिव-इन” रिलेशनशिप में हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य पराखंड में रहने की योजना बना है, तो कुछ चुनौतियाँ आपके मने आ सकती हैं। 6 फरवरी, 24 को, उत्तराखण्ड विधान सभा एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया, जिसमें भी नागरिकों के लिए उनके धर्म परवाह किए बिना विवाह, लाक, भूमि, संपत्ति और विरासत नूनों के लिए कोड शामिल थे। आदिवासी समुदायों पर लागू होगा। यह विधेयक 7 फरवरी राज्य विधानसभा द्वारा पारित या गया था और जब राज्य के व्यापाल अपनी सहमति दे देंगे यह कानून बन जाएगा। यूसीसी 22 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र का प्रमुख वादा था। विधेयक की भारी में उत्तराखण्ड सरकार ने 5 लाख से अधिक लाखत आरॉनलाइन सुझाव मांगने और एकत्र करने के बाद 740 पेज का मसौदा तैयार किया, कई सार्वजनिक मंच आयोजित किए और 60,000 से अधिक लोगों से बातचीत की। बिल तैयार किया। यूसीसी का अधिदेश व्यक्तिगत कानून बनाना और लागू करना था जो धर्म, लिंग और यौन अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू हों। वर्तमान में, विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून धर्मग्रंथों द्वारा शासित होते हैं और विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव को कवर करने वाले सार्वजनिक कानून से अलग होते हैं। जबकि भारत के सविधान का अनुच्छेद 25–28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने मामलों को बनाए रखने की अनुमति देता है, संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय

राष्ट्रीय नातया बनात समय सभा  
नागरिकों के लिए निदेशक सिद्धांतों  
और सामान्य कानून को लागू करे।  
प्रस्तावित विधेयक में बहुविवाह और  
बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध का  
प्रस्ताव है य सभी धर्मों में लड़कियों  
के लिए एक सामान्य विवाह योग्य  
आयु और तलाक के लिए मानक  
प्रक्रियाएं बेटों और बेटियों के लिए  
समान संपत्ति का अधिकार यैथ  
और नाजायज बच्चों के बीच अंतर  
को खद्दम करनाय मृत्यु के बाद  
समान संपत्ति अधिकार और गोद  
लिए गए और जैविक बच्चों को  
शामिल करनाय और "लिव-इन"  
रिश्ते से पैदा हुए बच्चे की वैधता।  
एक प्रतिगामी प्रस्ताव "लिव-इन"  
रिश्तों के संबंध में है, जहां पुरुष  
और महिलाएं शादी के बिना एक  
साथ रहने के लिए सहमत होते हैं।  
यूसीसी प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे  
रिश्ते में साझेदारों के लिए अपने  
अधिकार क्षेत्र में रजिस्टर को एक

राजस्ट्रार यह सुनाइचत करने के लिए एक "सारांश जांच" करेगा कि यह रिश्ता धारा 380 के तहत उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, जहां कम से कम एक व्यक्ति नाबालिग है, पहले से ही शादीशुदा है या "लिव-इन" रिश्ते में है। विवरण प्रस्तुत नहीं करने वालों को तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों होंगे। यदि संबंध समाप्त किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को भी एक बयान के साथ सूचित करना होगा। परित्याग के मामलों में, "लिव-इन" रिश्ते में रहने वाली महिला सक्षम अदालत के माध्यम से अपने साथी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। यह पहले से ही अक्षम और भ्रष्ट नौकरशाही पर एक बोझ है और मानता है कि अगर रिश्ता खत्म हो जाए तो महिलाएं आर्थिक रूप से एक लिव-इन संबंध दा भागदारों के बीच समानता मानता है, व्यवस्थित विवाह के विपरीत जहां पुरुषों से महिलाओं के लिए रोटी-विजेता और संरक्षक होने की उम्मीद की जाती है। राज्य का दावा है कि ऐसे "लिव-इन" रिश्तों में महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, या पुरुषों द्वारा उन्हें छोड़ देने के परिणाम ने ऐसे तंत्र के प्रस्ताव को प्रेरित किया है। हालाँकि, "लिव-इन" रिश्तों में, दो लोग, स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से, एक साथ आते हैं क्योंकि वे शादी करना चाहते हैं और इसके लिए तैयार नहीं हैं। यदि इरादा इन रिश्तों में महिलाओं की रक्षा करने का है, तो प्रस्तावित उपाय उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे और जब ये रिश्ते टूट जाएंगे, तो राज्य की सहायता के बिना, उन्हें भंग किया जा सकता है और किया जाएगा। जब भी राज्य को लाया जाएगा।

# जनता – पाक चुनाव में कोई विजेता नहीं

दिसीर पुतिन से दोस्ती करने लिए उनकी मास्को यात्रा। केस्तान में चुनावी ड्रामा जारी मतदान समाप्त होने के 48 घंटे भी 10 सीटों के नतीजे घोषित किये गये हैं। परिणामों में हरफेर आरोप लगाते हुए कई दावे पर किए गए हैं, या तैयारी में हैं, न्हें कथित तौर पर इमरान अर्थक स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा भारी त मिलने के बाद बदल दिया था। इस बार लगभग 47 पश्त त मतदान हुआ है, जबकि 18 के चुनाव में यह 51.1 प्रतिशत। थोड़े—बहुत बदलाव के साथ र्थी—वार घोषित सीटें इस प्रकार 5 पीएमएल (एन) 75य पीपीपी 96 के आसपास निर्दलीय गदातर इमरान खान समर्थक)य अच्य 31। हालांकि पाकिस्तान लेकिन चुनाव 266 सीटों के लिए होते हैं। इसके बाद आनुपातिक आधार पर 60 सदस्यों को नामांकित किया जाता है, जिसमें 50 महिलाएं और 10 अल्पसंख्यक सदस्य होते हैं। समस्या यह है कि इमरान खान के वफादारों ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह न मिलने के बाद निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की है। आनुपातिक ऐड—ऑन निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अब ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि आगे क्या होगा। जाहिर है, गठबंधन सरकार अपरिहार्य है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ, चौथे कार्यकाल के लिए प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन बनाने के लिए भुट्टो—जरदारी के नेतृत्व वाली

साथ—साथ सिंध स्थित एमकयूएम से संपर्क कर रहे हैं। पीपीपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो—जरदारी ने दावा किया है कि उनके बिना इस्लामाबाद और महत्वपूर्ण प्रांतों में कोई सरकार नहीं बन सकती। पीटीआई के अध्यक्ष गौहर अली खान ने इस्लामाबाद और पंजाब में सरकार बनाने की क्षमता का दावा किया। उनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव में जीत हासिल की है। उनके वफादार, हालांकि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय संसद में बाकी लोगों से अधिक हैं। हालाँकि, सेना पीटीआई के गठबंधन निर्माण को विफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ आपराधिक मामलों के चलते पीटीआई के पास प्रधानमंत्री

उम्मीदवार की कमी हो सकती है। इसके बजाय वे चतुराई से बिलावल को प्रधान मंत्री बनाने के लिए पीपीपी को समर्थन की पेशकश कर सकते थे। आखिरिकार, उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या तब कर दी गई जब सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ उनका समझौता खद्दाब हो गया। उस पड़यन्त्र का कभी भी विश्वसनीय ढंग से पर्दाफाश नहीं हो सका। हालाँकि, पीपीपी को एहसास होगा कि पीटीआई के साथ किसी भी समझौते का मतलब है कि गठबंधन को इमरान खान के कानूनी और राजनीतिक बोझ, विशेष रूप से पाकिस्तान के “डीप स्टेट” की दुश्मनी विरासत में मिलेगी। अधिक संभावित परिणाम पीएमएल (एन) और पीपीपी के बीच प्रधान मंत्री के रूप में नवाज शरीफ के साझा कार्यकाल के लिए समझौता कर सकते हैं, हालांकि ऐसे सौदे तब पटरी से उतर जाते हैं जब पहला कब्जाधारी अपने कार्यकाल के बीच में सत्ता सौंपने से इनकार कर देता है। भुट्टो-जरदारी कबीले को यह भी चिंता होगी कि भले ही नवाज शरीफ बूढ़े और शारीरिक रूप से अक्षम हों, लेकिन उनकी बेटी और उत्तराधिकारी मरियम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए शक्ति मजबूत कर सकती हैं। जनरल असीम मुनीर और उनके विरिष्ट सहयोगी निश्चित रूप से ऐसे गठबंधन में त्वरित परिवर्तन पसंद करेंगे जो मुखर हुए बिना कार्यात्मक हो। राष्ट्रपति के उप सचिव के रूप में इस लेखक को याद है कि जब मार्च 1987 में जिया-उल हक ने राष्ट्रपति जैल सिंह से मुलाकात की थी, तो पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में नवाज शरीफ उनके साथ थे। 1988 में राष्ट्रपति जिया-उल हक की मृत्यु ने नवाज शरीफ के लिए उच्च पद तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। वह 1990 में प्रधान मंत्री बने, लेकिन उन्हें मध्य कार्यकाल से बाहर कर दिया गया। वह 1997 में इस पद पर लौटे, यहां तक कि उन्होंने 1998 में अपने सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को भी चुना। दो साल बाद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गए, जिसके कारण कारगिल युद्ध हुआ और जनरल द्वारा किए गए तख्लापलट में उन्हें हटा दिया गया। मुशर्रफ, इसलिए, नवाज शरीफ सर्तक



